**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 2997**

**दिनांक 21 मार्च, 2018**

**अन्वेषी कार्य में नीतिगत बदलाव**

**2997. श्री अजय संचेतीः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अन्वेषण के क्षेत्र में एक नए मार्ग का सूत्रपात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्वेषण के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने में पूर्व की प्रणाली कितनी मददगार रही है; और

(घ) मौजूदा प्रणाली को प्रतिस्थापित करने संबंधी आवश्यकता का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

**(क) और (ख):** भारत सरकार ने दिनांक 10.03.2016 को हाइड्रोकार्बन अन्‍वेषण व लाइसेंस नीति को अनुमोदित किया है। यह नई अन्‍वेषण नीति पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक हाइड्रोकार्बन संसाधनों के अन्‍वेषण और दोहन के लिए एकल लाइसेंस उपलब्‍ध कराती है, एक खुली रकबा लाइसेंस प्रक्रिया के माध्‍यम से अन्‍वेषण रकबों को तैयार करने में छूट प्रदान करती है, एक नए राजस्‍व हिस्‍सेदारी मॉडल द्वारा प्रचालनीय स्‍वायत्‍ता बढ़ाती है, उत्‍पादित कच्‍चे तेल और प्राकृतिक गैस के विपणन और मूल्‍य निर्धारण की आजादी देती है, वर्धित अन्‍वेषण चरण उपलबध कराती है और साथ ही नेशनल डैटा रिपोज़टरी (एनडीआर) में उपलब्‍ध भू-वैज्ञानिक आंकड़े महैय्या कराती है। खुला रकबा लाइसेंस नीति (ओएएलपी) की कार्यप्रणालियों के लागू होने पर, रूचि की अभिव्‍यक्‍तियां (ईओआईज) प्राप्‍त करने के लिए दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 15 नवम्‍बर, 2017 तक प्रथम दौर खोला गया था। प्राप्‍त ईओआईज के आधार पर, 55 ब्‍लॉक तैयार किए गए और अंतरराष्‍ट्रीय बोली प्रक्रिया के लिए दिनांक 19 जनवरी, 2018 से बोली के लिए प्रस्‍तुत किए गए

**(ग) और (घ):** नई अन्‍वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) व्‍यवस्‍था में, एनईएलपी-I से एनईएलपी –IX में प्रदान किए गए ब्‍लॉकों के लिए वित्‍त वर्ष 2016-17 तक अन्‍वेषण और उत्‍पादन (ईएंडपी) क्रियाकलापों में 26203.80 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया गया था। एनईएलपी व्‍यवस्‍था के तहत, संविदाओं के निष्‍पादन के समय प्रचालन संबंधी कई मुद्दे सामने आए जिनके चलते प्रचालकों के साथ कई विवाद हुए, जिनमें अन्‍य बातों के साथ साथ लागत वसूली सीमा, प्रबंधन समिति द्वारा अनुचित हस्‍तेक्षप, अधिप्राप्‍ति संबंधी मुद्दे, निवेश गुणक का परिकलन करने के लिए अपनाई गई विधि, लागत कम रखने के लिए प्रचालक को कोई प्रोत्‍साहन नहीं दिया जाना शामिल है। इससे लाभ पेट्रोलियम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। एनईएलपी की प्रबंधन व्‍यवस्‍था के अनुभव और इसको लागू करने में पाई गई खामियों के आधार पर, सरकार ने हाईड्रोकार्बन अन्‍वेषण और लाइसेंस नीति (एचईएलपी) लागू की है।

\*\*\*\*